

24 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

स्वास्थ्य:

- जंक फूड को बाहर फेंकें, स्वस्थ खाने की प्लेट वापस लाएं:

शासन:

- PMAY-U योजना का सिंहावलोकन:

विज्ञान:

- भारत ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना कैसे बना रहा है?

F. प्रीलिम्स तथ्य:

- 'बढ़ती गर्भी की चपेट में महंगाई':
- नाबांड ने हरित वित्तपोषण जुटाने के लिए रणनीति का अनावरण किया:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

संपादकीय-द दिन्दू

संपादकीय:

जंक फूड को बाहर फेंकें, स्वस्थ खाने की प्लेट वापस लाएं:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

स्वास्थ्य:

विषय: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: एचएफएसएस खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने का मार्ग।

परिचय: भारत में पोषण परिवर्तन

- पारंपरिक, संपूर्ण भोजन-आधारित आहार से प्रसंस्कृत, उच्च कैलोरी वाले पश्चिमी आहार की ओर संक्रमण।
- जंक फूड की बढ़ती खपत आर्थिक प्रगति, शहरीकरण और आक्रामक विज्ञापन से जुड़ी है।
- स्वास्थ्य परिणामों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसे चयापचय संबंधी विकार शामिल हैं।

सरकारी पहल और कानूनी ढांचा:

- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जीवन के मौलिक अधिकार (fundamental right to life) को रेखांकित करता है।
- ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण 2.0 जैसी सरकारी पहल स्वस्थ भोजन और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं।
- स्कूलों में एचएफएसएस (वसा, नमक और शर्करा में उच्च) खाद्य पदार्थों के विपणन और खपत पर अंकुश लगाने के लिए एफएसएआई और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विनियम।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतियाँ:

- एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा: बेहतर विनियमन और प्रवर्तन की सुविधा के लिए एफएसएसएआई ([FSSAI](#)) को एचएफएसएस खाद्य पदार्थों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- फ्रंट-ऑफ़-पैक लेबलिंग (एफओपीएल): उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी सामग्री के बारे में सूचित करने के लिए पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य करना।
- स्वस्थ भोजन के लिए सब्सिडी: जंक फूड की तुलना में स्वस्थ खाद्य पदार्थों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की नीतियाँ।
- व्यवहार परिवर्तन अभियान: स्वस्थ आहार की आदतों और सावधानीपूर्वक खाने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और युवा वयस्कों को लक्षित शैक्षिक अभियान।

निष्कर्ष: स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता

- स्वस्थ भोजन के लिए एक "जन आंदोलन" या लोगों के आंदोलन की आवश्यकता है।
- सूचित भोजन विकल्पों को सकृष्टि करने और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए ईमानदार नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सारांश:

- प्रसंस्कृत, उच्च कैलोरी आहार की ओर भारत का पोषण परिवर्तन सरकारी कार्रवाई को प्रेरित करता है। कानूनी फैसलों और पहलों का उद्देश्य अस्वास्थ्यकर भोजन की खपत पर अंकुश लगाना है। रणनीतियों में एचएफएसएस खाद्य पदार्थों को परिभाषित करना, स्पष्ट लेबलिंग लागू करना, स्वस्थ विकल्पों पर सब्सिडी देना और व्यवहार परिवर्तन अभियान शामिल हैं।

PMAY-U योजना का सिंहावलोकन:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

शासन:

विषय: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: पीएमएवाई-यू के सामने आने वाली समस्याएं।

पीएमएवाई योजना:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों आवास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए 2022 तक सभी के लिए आवास ([Housing for All \(HfA\)](#)) हासिल करना है।
- इस योजना के उद्देश्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास, कमज़ोर वर्गों के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी और लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण के लिए सब्सिडी शामिल है।

इन-सीटू (स्वस्थानी) स्लम (गन्दी बस्ती) पुनर्विकास का प्रदर्शन:

- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। केवल 2,10,552 मकानों को मंजूरी दी गई है, जो वास्तविक जरूरत से काफी कम है। ₹29 बिलियन से अधिक के बजटीय निवेश के बावजूद, PMAY-U ने केवल 25.15% शहरी आवास की कमी को पूरा किया है, जबकि लगभग 40 लाख घरों की अभी भी कमी है।

चुनौतियाँ और असफलताएँ:

- सामाजिक आवास में अंतर को पाटने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- स्लम पुनर्विकास में लंबवत् वृद्धि के कारण अक्सर आवर्ती उपयोगिता लागत और सिकुड़ी हुई जगहों के कारण रहने की अव्यवहारिक स्थितियाँ पैदा हो गईं। (लंबवत् विकास (Vertical growth) का अर्थ है आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बढ़ना।)
- भूमि स्वामित्व के मुद्दे, सामुदायिक भागीदारी के बिना परियोजना नियोजन के लिए सलाहकारों पर निर्भरता, और शहर के मास्टर प्लान और पीएमएवाई-यू उद्देश्यों के बीच विसंगतियों ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की।

निवेश व्यय और सरकारी योगदान:

- पीएमएवाई-यू योजना में केंद्र का योगदान निवेश व्यय का 25%, लगभग 2.03 लाख करोड़ रुपये है।
- लाभार्थी परिवार निवेश में 60% का योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय सामूहिक रूप से ₹ 1.33 लाख करोड़ का योगदान करते हैं।
- योजना में सीमित सरकारी भागीदारी का उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी) और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) वर्टिकल्स में, जहां भूमि का स्वामित्व लाभार्थियों के पास रहता है।

सारांश:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लक्ष्य स्लम पुनर्विकास और किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। हालाँकि, इस योजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें इन-सीट स्लम पुनर्विकास में अपर्याप्त प्रदर्शन और सीमित सरकारी योगदान शामिल हैं।

भारत ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना कैसे बना रहा है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विज्ञान:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्दी की जिंदगी में प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारत में ईवी उत्पादन।

विवरण:

- 15 मार्च को, केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle (EV)) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी।
- इस नीति का लक्ष्य भारत को न्यूनतम निवेश सीमा ₹ 4,150 करोड़ के साथ ईवी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- यह टेस्ला और बीवाईडी जैसे वैश्विक ईवी निर्माताओं को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बाजार की मांग के अनुरूप स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख नीति प्रावधान:

- 35,000 डॉलर के सीआईएफ (लागत, बीमा और माल दुलाई) मूल्य के साथ पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयातित ईवी पर आयात शुल्क पांच साल के लिए घटाकर 15% कर दिया गया है, बशर्ते कि एक विनिर्माण इकाई तीन साल के भीतर स्थापित की गई हो।
- आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 40,000 इकाइयों की अधिकतम सीमा के साथ 6,484 करोड़ रुपये की शुल्क छूट या निवेश के समानुपाती, जो भी कम हो लागु होगी।
- निर्माताओं के लिए स्थानीयकरण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें तीसरे वर्ष तक 25% स्थानीयकरण और पांचवें वर्ष तक 50% हासिल करने की आवश्यकता है।
- स्थानीयकरण लक्ष्य और निवेश मानदंड पूरे नहीं होने पर निर्माताओं की बैंक गारंटी रद्द कर दी जाएगी।

घरेलू खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया:

- टाटा मोटर्स ने घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका से इस नीति का विरोध किया है।

- डेलॉयट इंडिया के रजत महाजन ने कहा कि यह नीति बाजार के उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने वाले ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के पक्ष में है।
- ₹ 29 लाख से नीचे के सेगमेंट में भारतीय खिलाड़ियों को आयात शुल्क में कटौती से लाभ होने की संभावना कम है।

बाजार संबंधी विचार और चुनौतियाँ:

- वैश्विक ईवी खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचे और उपयोग पैटर्न जैसी स्थानीय स्थितियों पर विचार करना चाहिए।
- दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में पैठ महत्वपूर्ण रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे की सीमाओं और रेंज की चिंता के कारण यात्री वाहन पिछड़ गए हैं।
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अनुसार, व्यापक ईवी अपनाने में सहायता के लिए भारत को 2030 तक अनुमानित 13 लाख चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता है।
- सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को विश्वसनीयता, स्थायित्व और सेवा समर्थन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- इसमें घरेलू मांग के साथ उत्पाद डिजाइन को संरेखित करने और ईवी अपनाने को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
- विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारतीय निर्माताओं को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त उत्पाद डिजाइन और प्रणालियां बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात होता है।

सारांश:

- भारत की नई ईवी नीति का लक्ष्य वैश्विक खिलाड़ियों और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित

करके उत्पादन को बढ़ावा देना है। हालाँकि, बुनियादी ढांचे की कमी और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र विकास की आवश्यकता सहित चुनौतियों के साथ घरेलू चिंताएँ बनी हुई हैं।

प्रौलिम्स तथ्य:

1. 'बद्रती गर्मी की चपेट में महंगाई'

प्रसंग:

- आरबीआई बुलेटिन ने चरम मौसम की घटनाओं और भूराजनीतिक तनाव के कारण मुद्रास्फीति के जोखिम की चेतावनी दी है।
- मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9% थी, जो पिछले दो महीनों में 5.1% थी।
- डिस्टी गवर्नर माइकल डी. पात्रा के नेतृत्व में अधिकारियों ने "अर्थव्यवस्था की स्थिति" शीर्षक वाले एक लेख में चिंता व्यक्त की है।

समस्याएँ:

- चरम मौसम की घटनाएं और भू-राजनीतिक तनाव मुद्रास्फीति जोखिम पैदा करते हैं।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation) ने ग्लोबल वार्मिंग और 2024 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना की चेतावनी दी है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि दर्शाते हैं।
- मीठे पानी की कमी के संकट की संभावना पर बल दिया गया है।
- ला निना (La Nina) के संभावित उद्भव के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जिससे भारत में भारी वर्षा हो सकती है।

महत्व:

- जनवरी 2024 से हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी से भारत की विकास आकांक्षाओं को समर्थन मिल रहा है।
- मार्च में मुख्य मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निचले स्तर पर थी, जो कि अवस्फीतिकारी मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है।
- मुद्रास्फीति (*inflation*) की गतिशीलता के बीच विकास के अवसर पैदा होते हैं।

2. नाबार्ड ने हरित वित्तपोषण जुटाने के लिए रणनीति का अनावरण किया:

प्रसंग:

- नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस (*Earth Day*) पर अपना 'जलवायु रणनीति 2030' दस्तावेज़ जारी किया है।
- इसका उद्देश्य वर्तमान हरित वित्त प्रवाह में कमी को उजागर करते हुए भारत की हरित वित्तपोषण की आवश्यकता को संबोधित करना है।

सम्बन्धित जानकारी:

- नाबार्ड (*NABARD*) का कहना है कि भारत को 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
- 2019-20 तक वर्तमान हरित वित्तपोषण ₹49 बिलियन है, जो आवश्यक राशि से काफी कम है।
- अधिकांश धनराशि शमन के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें बैंक क्षमता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता में चुनौतियों के कारण अनुकूलन और लचीलापन के लिए केवल ₹5 बिलियन ही आवंटित थे।

महत्व:

नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:

- सभी क्षेत्रों में हरित क्रण में तेजी लाना, व्यापक बाजार-निर्माण भूमिका, आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना।
- डीएलएफ जैसे अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सतत विकास का संकल्प लिया।
- डीएलएफ शून्य-निर्वहन जल प्रणाली और सीवेज उपचार संयंत्र, प्रतिदिन लाखों लीटर पानी का पुनर्चक्रण और स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव कम करने जैसी प्रथाओं को लागू करता है।
- लगातार तीन वर्षों तक डॉव जोन्स स्टेनेबिलिटी इंडेक्स में डीएलएफ का शामिल होना पर्यावरण, सामाजिक और शासन उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- डीएलएफ के संयुक्त एमडी, आकाश ओहरी, जल पुनर्चक्रण, बागवानी का समर्थन, माध्यमिक जल उपयोग और झील पुनःपूर्ति में कंपनी के प्रयासों पर जोर देते हैं, जिससे भूजल निर्भरता कम होती है और हरियाली संरक्षण को प्राथमिकता मिलती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कितनी योजनाएँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं/हैं?

1. मिशन पोषण 2.0
2. मिशन वात्सल्य
3. मिशन शक्ति

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

- ये तीनों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत व्यापक योजनाएँ (umbrella schemes) हैं।

प्रश्न 2. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PMAY-U को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तत्त्वावधान में क्रियान्वित किया जाता है।

2. मिशन का व्यापक लक्ष्य सभी पात्र शहरी परिवारों को "पक्के" (टिकाऊ और स्थायी) घर प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार ने हाल ही में भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है।

2. यह नीति मोटे तौर पर वैश्विक ईवी निर्माताओं के लिए भारतीय बाजारों में प्रवेश का रास्ता साफ करती है।

3. पात्रता के लिए न्यूनतम ₹ 10,000 करोड़ का निवेश आवश्यक है।

इउपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

- पात्रता के लिए न्यूनतम ₹ 4,150 करोड़ का निवेश आवश्यक है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अल नीनो और ला नीना जटिल मौसम पैटर्न हैं जो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं।
2. अल नीनो घटना हर 2 साल में होने वाला एक नियमित चक्र है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

व्याख्या:

- अल नीनो घटना कोई नियमित चक्र नहीं है, इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और ये दो से सात साल के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती हैं।

प्रश्न 5. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पीएमआई निजी क्षेत्र की कंपनियों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त होता है।

2. पीएमआई वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

- पीएमआई निजी क्षेत्र की कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों से प्राप्त होता है और वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए, एवं उन व्यापक रणनीतियों का सुझाव दें जिन्हें इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए नियोजित किया जा सकता है। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-2, स्वास्थ्य]

(Evaluate the effectiveness of current government policies aimed at curbing the consumption of unhealthy foods, and suggest comprehensive strategies that can be employed to reverse this trend. (10 marks, 150 words) [GS-2, Health])

प्रश्न 2. भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हालिया नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-3, अर्थव्यवस्था] (Critically analyze the recent policy approved by the Indian government to promote India as a manufacturing hub for electric vehicles (EVs). (10 marks, 150 words) [GS-3, Economy])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर किलक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

